

प्रेषक,

डी0एस0 गब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

जुलाई

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 02 जून, 2015

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर पंचायत, पुरोला (उत्तरकाशी) को अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, नगर पंचायत, पुरोला के पत्रांक-मेमो/2-लेखा-दैवी आपदा से क्षति योजना, दिनांक 21.03.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध कराते हुए अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, पुरोला (उत्तरकाशी) को निम्नलिखित 02 निर्माण कार्यों हेतु कार्यवार कुल ₹5.00 लाख (रुपये पाँच लाख मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	स्वीकृत धनराशि
1.	वार्ड नं0 6 में आनन्द रावत के मकान से शोभाराम नौटियाल के मकान तक खडिंजा/रास्ते की दीवार का निर्माण।	2.50
2.	कन्जेला नामे तोक में सुरक्षा दीवार/नहर निर्माण कार्य।	2.50
योग-		5.00

2- उपरोक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है :-

- उक्त धनराशि ₹5.00 लाख (रुपये पाँच लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, पुरोला (उत्तरकाशी) को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
- स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
- सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।
- कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशाली अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

- VIII. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- IX. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले **Construction Agreement** में एक वर्ष का **Defect Liability Period** तथा 3 वर्ष तक अनुस्क्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
- X. धनराशि का दिनांक 31-3-2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 88/XXVII(2)कार्य/2005, दिनांक 21.02.2005 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप जारी किये जा रहा है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी-S.1507.13002.01 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी०एस० गर्बाल) -
सचिव।

सं०-704 (1)/IV(2)-श०वि०-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, पुरोला।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।